POSTAL REG. NO. RJ/JPC/M-17/2012-14 (RNI.REG.NO. 39658/1983) # ग्रा.ग./2014/अंक 09

कृपया इसे चौराहे पर चिपकाइये

मासिक प्रेषण दि. 8 सितम्बर, सी.एस.ओ., आरएमएस गाँधी नगर, जयपुर-15

ग्राम गदर

वर्ष 1983 से प्रकाशित

8 सितम्बर, 2014 मूल्य 50 पैसे

आपके नाम चिट्ठी

जयपुर से जोग लिखी प्रदीप महता का सबको राम-राम/सलाम ! प्रदेश में राज्य सरकार ने आपके द्वार कार्यक्रम के तहत भरतपुर, बीकानेर और उदयपुर संभागों का दौरा किया। इन संभागों में आला अफसरों की टीमों के साथ खुद मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और विभागों के मंत्रीगण पंचायत स्तर तक आमजन की समस्याओं, अभाव अभियोगों और सरकारी अमले की कमजोरियों से साक्षात रूबरू हुए।

जनसुनवाई शिविरों में भारी भीड़ देखी गई। लोगों ने खुलकर स्थानीय मुद्दों एवं समस्याओं को उजागर किया और समय पर काम न होने की ढेरसारी शिकायतें भी दर्ज कराई।

मुख्यमंत्री व मंत्रियों ने लोगों के समूह के बीच सरकारी अफसरों व मातहतों को खूबजोर की फटकार भी लगाई और उन्हें आमजन की समस्याओं के अतिशीघ्र समाधान करने के सख्त निर्देश भी दिए।

सरकार को इस रूप में अपने सामने पाकर लोगों के चेहरे अति विश्वास से खिल उठे। उन्हें लगा कि अब उनके काम होने में जरा भी ढील नहीं होगी। लोगों ने सरकार द्वारा की गई इस पहल को एक सुधारवादी कदम माना है। लेकिन सामने आने लगा है कि जैसे ही सरकार इन संभागों से रवाना हुई, सरकारी अधिकारी हो या कर्मचारी फिर अपने पुराने ढर्रे पर आ गए हैं। इससे अच्छे माने जाने वाले इस कार्यक्रम की फ़जीयत होते देर नहीं लगेगी।

अतः कार्यक्रम के सही क्रियान्वयन के लिए 'फॉलोअप' तथा 'मॉनिटरिंग' व्यवस्था को मूर्तरूप देने के साथ-साथ कई सुधार किए जाने की दरकार है। कार्यक्रम में स्थानीय सामाजिक और स्वयंसेवी संस्थाओं को भी सहभागी बनाया जा सकता है।

अपनी सम्पत्ति की सुरक्षा चाहते हैं, तो वसीयत जरूर लिखें !

गांवों में कम पढ़े-लिखे लोग वसीयत लिखना नहीं जानते। वसीयत का अर्थ है किसी व्यक्ति द्वारा अपनी सम्पत्ति के बंटवारे के बारे में अपनी इच्छा की लिखित, कानूनी व वैधानिक घोषणा करना। हर पुरूष व महिला को अपनी इच्छा के मुताबिक वसीयत करने व लिखने का अधिकार कानून में दिया गया है।

- वसीयत खुद लिखी जा सकती है या अनपढ़ होने पर किसी विश्वासपात्र व्यक्ति से लिखवाई जा सकती है। लिखवाने के बाद उसे ध्यान से दुबारा पढ़ाकर सुनना चाहिए। इसके बाद अपने हस्ताक्षर या अंगूठा निशानी करनी चाहिए। वसीयत सादा कागज पर भी लिखी जा सकती है। वसीयत लिखने व लिखाने वाला व्यक्ति स्वस्थ्य चित्त होना चाहिए।
- वसीयत पूरी तरह से लिखाने के बाद उस पर दो जानकार व्यक्तियों के हस्ताक्षर कराने चाहिए। वसीयत का सुरक्षा की दृष्टि से पंजीयन भी करा सकते हैं। वसीयत करने वाला व्यक्ति जब चाहे अपनी वसीयत को परिवर्तित भी कर सकता है। वसीयत करते समय यह खास तौर से ध्यान में रखना चाहिए कि उसकी सम्पत्ति सही लोगों के पास जा रही है।
- यदि वसीयत नहीं की गई हो, तो ऐसी सम्पत्ति पर उस व्यक्ति के लड़के-लड़कियों को बराबर सम्पत्ति प्राप्त करने का हक कानून में दिया गया है। पुराने कानून में लड़कियों का सम्पत्ति में हिस्सा नहीं था, लेकिन अब उन्हें सम्पत्ति में बराबर की सम्पत्ति प्राप्त करने का हक दिया गया है।

छात्र की टीसी नहीं देना स्कूल संचालक को भारी पड़ा

जोधपुर निवासी खेमाराम जाट ने भदवासिया क्षेत्र स्थित संध्या शिक्षा सदन माध्यमिक स्कूल के प्रिंसिपल के खिलाफ जिला उपभोक्ता मंच (प्रथम) में परिवाद दर्ज कराया। परिवाद में बताया गया कि उक्त स्कूल में उनकी बेटी निर्मला 9वीं और पुत्र वीरेन्द्र 7वीं कक्षा में पढ़ते थे। वह बच्चों को 2013-14 में दूसरे स्कूल में प्रवेश दिलाना चाहते थे। इसलिए उन्होंने टीसी के लिए आवेदन किया। लेकिन स्कूल के प्रिंसिपल ने यह कह कर टीसी देने से मना कर दिया कि उनके स्कूल में छात्र संख्या कम हो जाएगी। टीसी नहीं मिलने से दोनों बच्चों का दूसरे स्कूल में प्रवेश नहीं दिलाया जा सका। इससे बच्चों की एक साल की पढ़ाई खराब हो गई।

मामले की सुनवाई पर उपभोक्ता मंच ने स्कूल संचालक को सेवा का दोषी मानते हुए कहा कि टीसी नहीं मिलने से बच्चों का बहुमूल्य एक साल बर्बाद हुआ है। मंच ने स्कूल संचालक पर 50 हजार रुपए का जुर्माना लगाया है, साथ ही बच्चों के अभिभावक खेमाराम को 20 हजार रुपए मानसिक क्षतिपूर्ति के रूप में भी अदा करने के आदेश दिए हैं।

भ्रष्टाचार बर्दास्त नहीं-मोदी

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने भ्रष्टाचार के खिलाफ युद्ध छेड़ने की घोषणा करते हुए कहा है कि न मैं खुद खाऊंगा, न खाने दूंगा। किसी भी स्तर पर भ्रष्टाचार को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि पिछले कुछ दशकों से राज्यों और केन्द्र में हो रहे भ्रष्टाचार ने देश के विकास को प्रभावित किया है। हम भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ेंगे, ताकि धन का इस्तेमाल गरीबों के कल्याण और विकास के लिए किया जा सके।

कश्मीर में 45 मेगावाट बिजली परियोजना का उद्घाटन और लेह-कारगिल-श्रीनगर बिजली पारेषण लाइन की आधारशिला रखने के बाद जनसभा में यह घोषणा करते हुए उन्होंने कहा कि हमारे पास सब कुछ है, इसके बावजूद देश में गरीबी बढ़ रही है।

हालांकि उन्होंने कहा कि देश में ईमानदार अधिकारी और लोग भी हैं, जो ईमानदारी के साथ अपना कर्तव्य निभा रहे हैं। सेना के जवान हमें प्रेरणा देते हैं। दैनिक जीवन की अनेक परेशानियों और संघर्ष झेलने के बावजूद सैनिक अपने कर्तव्य के पथ पर अडिग रहते हैं।

भामाशाह योजना शुरू

मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने 15 अगस्त को उदयपुर में हुए राज्य स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह में भामाशाह योजना की शुरूआत की। उन्होंने योजना के तहत आठ महिलाओं को स्मार्ट कार्ड देते हुए इस साल योजना के लिए 600 करोड़ रुपए देने की घोषणा की। भामाशाह योजना पर प्रकाश डालते हुए उन्होंने कहा कि यह योजना देश की सबसे बड़ी फाइनेंशियल स्कीम है।

इस योजना से प्रदेश की एक करोड़ 50 लाख महिलाओं को मल्टीपरपज स्मार्ट कार्ड के जरिए सरकार की विभिन्न योजनाओं का लाभ मिलेगा। योजना के तहत परिवार की महिला मुखिया के नाम से खुले खाते में राशि जमा होगी। महिला मुखिया के नाम से खुले बैंक अकाउंट से महिलाओं को ताकत मिलेगी। भामाशाह योजना के लिए एनरोलमेंट की प्रक्रिया चालू कर दी गई है, जो अक्टूबर तक चलेगी।

मनरेगा के तहत रिचार्ज होगा भू-जल

प्रदेश के डार्क जोन घोषित क्षेत्रों में बसे गांवों में पीने योग्य पानी का संग्रहण कर भूजल को रिचार्ज किया जाएगा। राज्य सरकार द्वारा गुजरात की तर्ज पर गांवों में जल संग्रहण की योजना तैयार की जा रही है। जल्द ही जिला कलेक्टरों के माध्यम से तैयार प्लान को मंजूरी दे दी जाएगी।

ग्राउंड वाटर रिचार्ज करने की प्लानिंग इस तरह की जाएगी कि जरूरत पड़ने पर गांव को कम से कम एक साल के लिए पीने योग्य पानी की सप्लाई हो सके। यदि गांव के पास नदी या नहर क्षेत्र है तो जल पुनर्भरण ढांचा उसके नजदीक बनाया जाएगा। गांवों में बनने वाले इन ढांचों में बारिश के पानी को स्टोर करने की व्यवस्था की जाएगी। क्षेत्रीय जनप्रतिनिधियों और ग्राम पंचायतों से प्राप्त सुझावों को भी इसमें शामिल किया जाएगा।

छात्राओं को मिलेंगी साइकिल

मुख्यमंत्री की बजट घोषणा संख्या 155 के अनुसार सरकारी स्कूलों की 9वीं कक्षा में प्रवेश लेने वाली छात्राओं को निःशुल्क साइकिलें दी जानी है। चूंकि विधानसभा में बजट घोषणा जुलाई में होने से छात्राओं तक साइकिल पहुंचने में करीब छह महीने का समय लग सकता है।

साइकिल खरीद की सरकारी प्रक्रिया काफी लम्बी होती है। टैंडर जारी करने से लेकर कंपनी से सप्लाई होने में ही काफी समय लग जाता है। पहले बजट मार्च में आता था तब भी जुलाई माह तक छात्राओं को साइकिल नहीं मिल पाती थी। देर से साइकिल मिलने के कारण छात्राओं के स्कूल आने-जाने में साइकिल का उपयोग अगले शिक्षा सत्र में ही हो पाएगा।

श्री योजना में गुजरात मॉडल

ग्रामीण विकास के लिए श्री योजना को राज्य सरकार गुजरात की तर्ज पर लागू करने पर विचार कर रही रही है। योजना में आधारभूत ढांचा विकास के साथ ही बेहतर सेवा अदायगी पर पूरा जोर दिया गया है। गांवों में सेनिटेशन, स्वास्थ्य, शिक्षा, बिजली, पानी की व्यवस्था पर ज्यादा ध्यान दिया जाएगा।

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग के प्रमुख सचिव श्रीमत पांडेय ने यह जानकारी देते हुए बताया कि पहले चरण में पांच हजार से अधिक आबादी वाले गांवों को इस योजना में सम्मिलित किया जा रहा है। शेष गांवों को दूसरे चरण में शामिल किया जाएगा। यह योजना भरतपुर संभाग में लागू की जा चुकी है तथा शेष राज्य में इसे दो अक्टूबर से लागू किया जाएगा।

पेड़ों के संरक्षण की अनूठी पहल

राजसमंद जिले की निर्मल ग्राम पंचायत पिपलांत्री में पर्यावरण संरक्षण के लिए अनूठी पहल की गई है। यहां पंचायत स्तर पर लिए गए निर्णय के बाद से बेटी के जन्म पर गांवों में दस पौधे लगाए जा रहे हैं।

हाल ही रक्षा बन्धन पर गांव की बेटियों ने पेड़-पौधों को रक्षासूत्र बांध कर इनके संरक्षण और संवर्धन का संकल्प लेकर एक मिसाल पेश की है। प्रदेश की अन्य पंचायत स्तर पर ऐसे निर्णय लेकर पर्यावरण की सुरक्षा का बीड़ा उठाया जा सकता है।

बन्द नहीं होगी मुफ्त दवा योजना

राज्य के चिकित्सा मंत्री राजेन्द्र सिंह राठौड़ ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने गरीबों की सोचते हुए पूरे देश में मुफ्त दवा योजना चालू करने की घोषणा की है। प्रदेश में भी निःशुल्क दवा योजना बन्द नहीं की जाएगी। मुफ्त दवा योजना का लाभ केवल बीपीएल और अंत्योदय कार्ड धारकों को ही देने की लगाई जा रही अटकलों पर इससे विराम लग गया है।

उन्होंने बताया कि दवाओं की खरीद के लिए बजट जारी कर दिया गया है। अस्पतालों में दवाओं की कोई कमी नहीं आने दी जाएगी। चिकित्सा मंत्री ने यह जानकारी बांसवाड़ा में सरकार आपके द्वार कार्यक्रम के दौरान दी है।

अच्छे दिन कब आएंगे?

जनता ने बहुमत से भाजपा को सत्ता का तोहफा दे दिया। मोदी जी ने जनता को भरोसा दिया कि अच्छे दिन आने वाले हैं। उनके पास जादू की छड़ी नहीं है। उनके पास ऊर्जा है, टीम है, मौलिक चिन्तन है, लेकिन सुधार तो तभी संभव है जब लोगों का राष्ट्रीय चरित्र जागृत होगा।

इसके लिए सभी के हृदय में शुद्ध आचरण, कर्तव्य बोध और देश प्रेम की भावना पैदा करनी होगी। आज किसी को भय नहीं है। जिन देशों में भय है वहां अनुशासन है। भारतीय सिंगापुर में अनुशासित रह सकता है, लेकिन भारत आने पर स्वतंत्र हो जाता है ?

-डॉ. के.एम.शर्मा, एडवोकेट, पाली

सोलर लाइट खरीद की होगी जांच

राज्य सरकार प्रदेश की सभी 9 हजार 177 ग्राम पंचायतों में सोलर लाइट खरीद की जांच कराएगी। पैसे का गलत उपयोग पाए जाने पर उसकी वसूली भी की जाएगी।

ग्रामीण विकास मंत्री गुलाब चन्द कटारिया ने विधानसभा में विधायक मोहनलाल गुप्ता के ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर यह जानकारी देते हुए कहा कि खरीद प्रक्रिया और गड़बड़ी में जितने भी लोग शामिल होंगे, उनको दण्ड दिया जाएगा। फिलहाल सोलर लाइट खरीद पर रोक लगा दी गई है। राज्य के 19 जिलों की प्राप्त सूचना के आधार पर 1182 ग्राम पंचायतों में अधिक दर पर सोलर लाइटें खरीदी गई हैं। इससे प्रथम दृष्टया 11 करोड़ 29 लाख रुपए अधिक खर्च किए गए हैं।

सरपंच पति का दखल तो चुनाव रद्द

अब पंचायतों में यदि महिला के बदले उसके पति अर्थात सरपंच पति किसी तरह का दखल देते पकड़े गए तो महिला का चुनाव रद्द हो सकता है। केन्द्र सरकार इसके लिए प्रस्ताव तैयार कर रही है।

अतः ऐसे पतियों को अब सतर्क हो जाने की जरूरत है, जिनकी पत्नियां सरपंच या प्रधान हैं, लेकिन पंचायत के फैसले वे खुद लेते हैं। अक्सर शिकायतें आती है कि पत्नी के पद का फायदा उठा कर सरपंच पति योजनाओं में धन कमाने का रास्ता निकालते हैं।

जिला स्तर पर उपभोक्ता हैल्पडेस्क

खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति राज्यमंत्री हेमसिंह भडाना ने कहा है कि उपभोक्ताओं को समुचित जानकारी देने के लिए राज्य व जिला स्तर पर उपभोक्ता विषयक विभागों में हैल्पडेस्क और उपभोक्ता शिकायत निवारण अधिकारी नियुक्त किए जाएंगे। राज्य उपभोक्ता संरक्षण परिषद की बैठक में उन्होंने कहा कि विद्युत, पानी, खाद्य, बैंकिंग, बीमा, शिक्षा व कृषि आदि विभागों में समस्याओं के समाधान के लिए जानकारी उपलब्ध करवाने के लिए व्यवस्था की जाएगी।

उपभोक्ता शिकायत निवारण प्रकोष्ठ

जागो ग्राहक जागो

'कट्स' सेंटर फॉर कन्ज्यूमर एक्शन, रिसर्च एण्ड ट्रेनिंग (कट्स कार्ट) द्वारा उपभोक्ताओं की शिकायतों के निवारण करने, शिकायतों से संबंधित सूचना एवं सलाह सेवाएं देने के लिए एक प्रकोष्ठ बनाया हुआ है। कोई भी उपभोक्ता अपनी शिकायत या समस्याओं के बारे में स्वयं व्यक्तिश कार्यालय समय में डी-218, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर स्थित कार्यालय में सम्पर्क कर सकता है अथवा नीचे लिखे फोन, फैक्स व ईमेल के माध्यम से अपनी शिकायत प्रेषित कर सकता है।

30 1983 2012 CUTS International

फोन: 141-2282823, 2282482, 5133259, फैक्स: 141-4015395
ईमेल: cart@cuts.org, वेबसाइट: www.cuts-international.org/cart

कट्स कार्ट

सम्पादक, प्रकाशक एवं मुद्रक स्वत्वाधिकारी प्रदीप एस महता के लिए भालोटिया प्रिन्टर्स, जयपुर से प्रकाशित।

'अक्षत टावर', डी-217, भास्कर मार्ग, बनीपार्क, जयपुर 302016 फोनः 228 2821 से 23 फैक्सः 0141-228 2485

कम्पोजिंग एवं लेआउट राजकुमार त्रिवेदी, 'कट्स' जयपुर